

प्रश्न सं. [क. 710]

विधानसभा अतायांकित प्रश्न क्रमांक 710							परिशिष्ट-अ	
क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किस माध्यम से प्राप्त हुई	रिजिस विषय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई (अवेध रेत परिवहन/अन्य खनिज अवेध परिवहन/अवेध नाका	शिकायत का साक्षि विवरण	की गई कार्रवाई	व्या शिकायतक र्ता के बयान दर्ज किए गये	रिमांक
1	17/06/2024	माननीय विधायक श्री मुरली भंवरा	लिखित	अवेध नाका	विधानसभा क्षेत्र वागली के धनतालाब से अवेध खनिज नाको को हटाने के संबंध में।	उक्त शिकायत के संबंध में जांच करवाई गई जांच अनुसार देवास जिले में संघालित रेत नाके धनतालाब दीपगांव भौरसा को बंद किये जाने हेतु सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 839 दिनांक 26/07/2024 से पत्र जारी किया गया।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं होने से बयान दर्ज नहीं किये गये।
2	22/11/2024	श्री चंचल कुमार भारती	लिखित	अवेध रेत परिवहन	खातेगांव के तमखान नर्मदा घाट से अवेध परिवहन के संबंध में।	उक्त शिकायत की जांच की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर खनिज नियमानुसार 25000 राशि वसूल की गई।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं होने से बयान दर्ज नहीं किये गये।
3	01/9/2025	श्री अकबर पिता गबू खां	लिखित	अवेध रेत परिवहन	माँ नर्मदा के तमखान घाट पर अवेध उत्खनन होने के संबंध में।	उक्त शिकायत की जांच की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है।	हाँ	

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

4	02/01/2026	माननीय विधायक डॉ. श्री हीरालाल अलावा	लिखित	अवैध नाका	देवास जिले में संघालित खनिज जांच नाके के संबंध में।	माननीय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 132 दिनांक 21/01/2026 से सूचना पत्र जारी किया गया एवं प्रथम दृष्टता जांच में ये पाया गया की नाके पर कोई भी अवैध वस्तु करते हुये नहीं पाया गया। शिकायत में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से शिकायत निरधार पाई गई।	नहीं	शिकायतकर्ता जांच के दौरान नाके पर उपस्थित नहीं होने से व्याज दर्ज नहीं किये गये।
---	------------	---	-------	--------------	---	---	------	--

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज संयोजन विभाग

Shelkar

(2)

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेश हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स - 0755-2551795
E-mail - dirgeomn@nic.in

क्रमांक - 13130
प्रति,

भोपाल, दिनांक - 04/10/23

कलेक्टर
जिला -
मध्यप्रदेश।

विषय :- जाँच चौकियों की स्थापना और अभिवहन किए जा रहे खनिजों का तोलन तथा निरीक्षण बाबत।

संदर्भ :- राज्य खनिज निगम लिमिटेड का प्रस्ताव दिनांक 29/09/2023 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 08/04/2022 में प्रकाशित नियम 7.

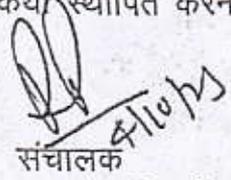
संदर्भित विषयांतर्गत प्रदेश में रेत धारित जिलों में रेत खदान समूहों की ई-निविदा सह नीलामी में 42 जिलों में से 33 जिलों में सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. चयनित किये जा चुके हैं तथा म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं जिला स्तर से अनुबंध निष्पादन कराया जा चुका है एवं चयनित सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. (माइन डेवलपर कम ऑपररेटर), म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं संबंधित कलेक्टर से त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। ई-निविदा सह नीलामी उपरांत सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. द्वारा रेत खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु रेत खनिज जाँच नाकों को स्थापित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 7 में जाँच नाकों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैं :-

"जाँच चौकियों की स्थापना और अभिवहन किए जा रहे खनिजों का तोलन तथा निरीक्षण - (1) यदि राज्य सरकार विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण पर रोक लगाने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह लिखित में आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या किन्हीं स्थानों पर जाँच चौकियां स्थापित करने का निर्देश दे सकेगी। किसी जाँच चौकी के स्थापित किए जाने को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा;

परन्तु जिले में किसी भी स्थान पर जाँच हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अस्थाई व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए राजपत्र में किसी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी।"

अतः उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आप जिले के सफल निविदाकार/एम.डी.ओ. के प्राप्त आवेदन एवं अन्य सुझाव अनुसार रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण की रोकथाम हेतु जिले में स्थान चिन्हित कर अस्थाई जाँच चौकियाँ स्थापित करने के संबंध में परीक्षण कर समुचित कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


संचालक

(प्रशासन एवं खनिकर्म) 


(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज सचिव विभाग